Ojaank Gurukul | IAS

चीन की भारत को घेरने की रणनीति

चीन हर एक रणनीति अपना रहा है भारत को घेरने के लिए। श्रीलंका और मालदीव्स में शी जिनपिंग की बड़ी रणनीति विफल हुई, लेकिन अब चीन बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक माहौल का फायदा उठाना चाहता है।

इस प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे चीन दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है और भारत इसका कैसे मुकाबला कर रहा है। हम मालदीव्स और श्रीलंका में चीन की विफलता के कारणों और बांग्लादेश में उसकी बढ़ती उपस्थिति का विश्लेषण करेंगे।

by OJAANK IAS

मालदीव्स में चीन की विफलता

1

2013-2018

अब्दुल्ला यमीन के शासनकाल में मालदीव्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ, जिससे $1.4 बिलियन का कर्ज हो गया।

2

2018

भारत समर्थक इब्राहिम सोली सत्ता में आए, जिससे भारत-मालदीव्स संबंध मजबूत हुए।

3

2023

"इंडिया आउट" अभियान के साथ मुईज़ू के चुनाव से भारत को झटका लगा।

4

वर्तमान स्थिति

आर्थिक समस्याओं के कारण मुईज़ू को बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है और वह भारत से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीलंका में चीन का डेट ट्रैप

$5 बिलियन का कर्ज

2005-2022 के बीच राजपक्षे शासन के दौरान चीन से भारी कर्ज लिया गया

हंबनटोटा पोर्ट का अधिग्रहण

कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण श्रीलंका ने पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया

आर्थिक संकट

2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य हो गया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए

श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद भारत ने लगभग $4 बिलियन की सहायता प्रदान की। अब श्रीलंका चीन, भारत, जापान और अमेरिका के बीच संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच पहला रक्षा समझौता हुआ।

बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव

$4B

चीनी कर्ज

बांग्लादेश पर चीन का वर्तमान कर्ज जो लगातार बढ़ रहा है

5

भारतीय राज्य

बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या

1

सबमरीन बेस

चीनी सहायता से कॉक्स बाजार में निर्मित सबमरीन बेस

चीन बांग्लादेश में परिवहन, बंदरगाह, बिजली, दूरसंचार और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इसके अलावा, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में चीनी सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसमें पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और रडार शामिल हैं।

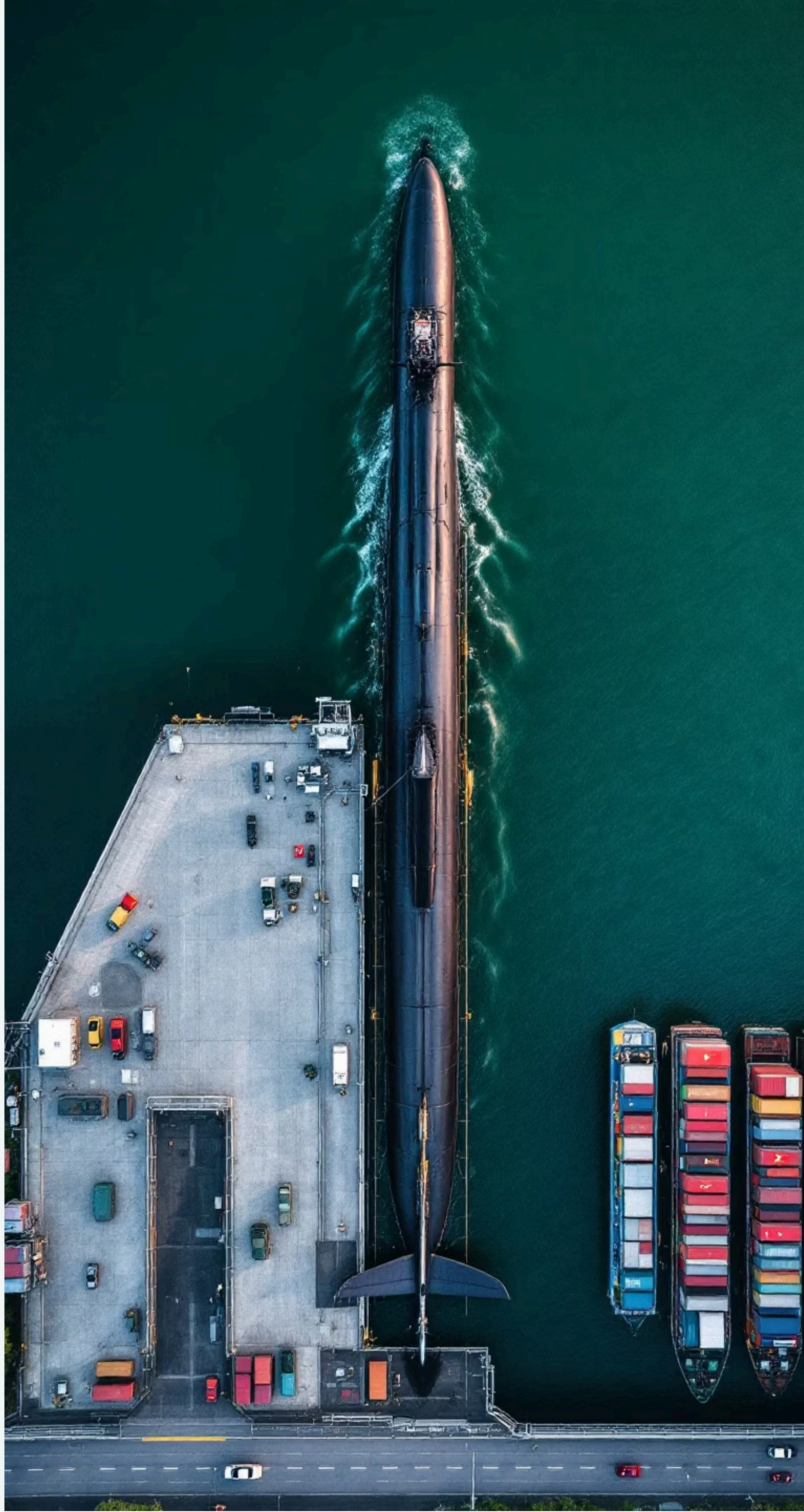

Fill This Form and Apply Now 👇🏻👇🏻👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

बांग्लादेश में चीन के रणनीतिक लक्ष्य

बंदरगाहों तक पहुंच

कॉक्स बाजार सबमरीन बेस और चटगांव पोर्ट तक पहुंच प्राप्त करना

सैन्य उपस्थिति

बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक उपस्थिति स्थापित करना

व्यापारिक प्रभुत्व

मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से बांग्लादेशी बाजार पर नियंत्रण

राजनीतिक प्रभाव

बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों और थिंक टैंक को प्रभावित करना

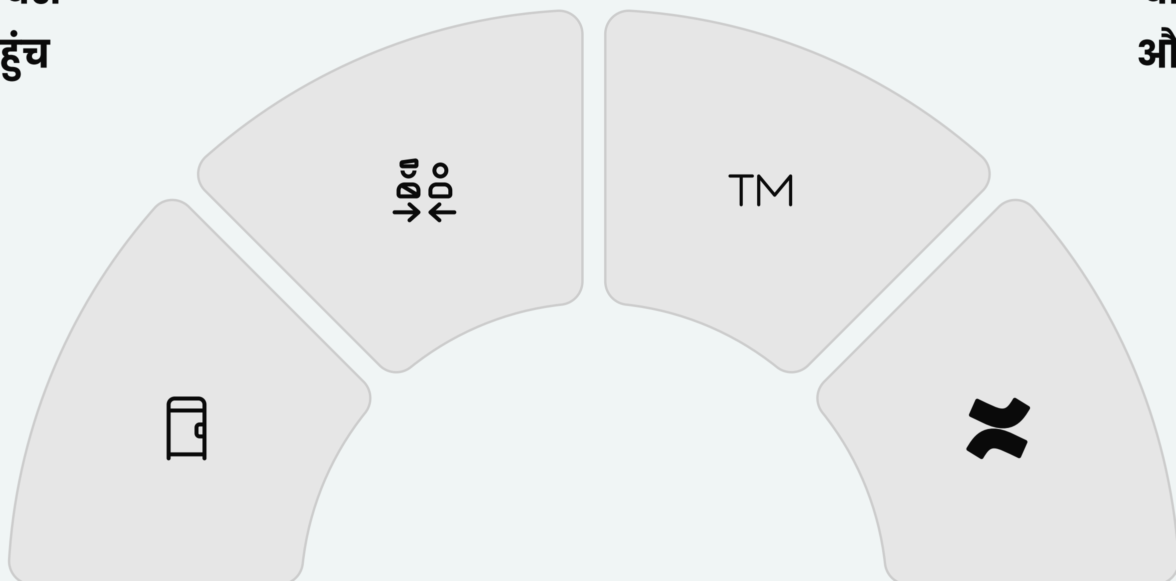

चीन कॉक्स बाजार सबमरीन बेस का द्विउपयोगी उपयोग कर सकता है - वाणिज्यिक और सैन्य दोनों। चटगांव पोर्ट तक पहुंच भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खतरा बन सकती है। चीन "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति के तहत भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए चिंता के कारण

भौगोलिक निकटता

बांग्लादेश पांच भारतीय राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा) के साथ सीमा साझा करता है, जिससे चीनी उपस्थिति विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खतरा बन जाती है।

नौसैनिक घेराबंदी

कॉक्स बाजार में चीनी उपस्थिति बंगाल की खाड़ी में चीन को सीधी नौसैनिक पहुंच प्रदान करेगी, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती है।

आर्थिक घेराबंदी

चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति के तहत ग्वादर, हंबनटोटा, म्यांमार और अब कॉक्स बाजार में उपस्थिति भारत को आर्थिक रूप से घेरने का प्रयास है।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना बढ़ने की संभावना है। यूनुस के हालिया बयान, विशेष रूप से "लैंड लॉक्ड" पूर्वोत्तर के बारे में, चीनी प्रचार को बढ़ावा देते हैं और सुझाव देते हैं कि भारत बांग्लादेश पर निर्भर है।

भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी

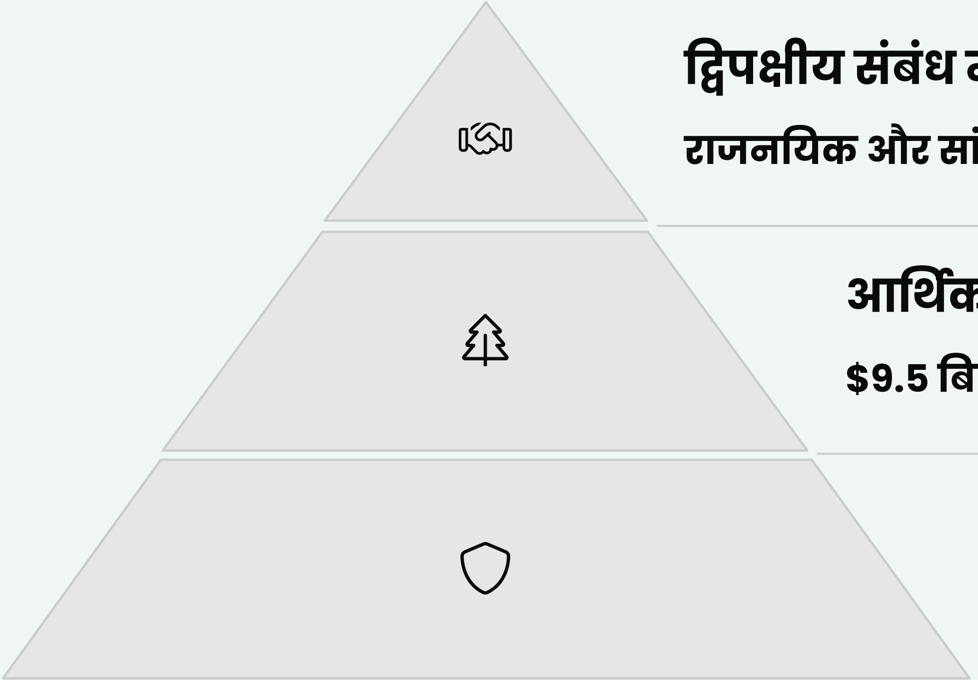

द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना

राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना

आर्थिक सहयोग

$9.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन और बुनियादी ढांचे में निवेश

रक्षा सहयोग

संयुक्त अभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण

भारत ने बांग्लादेश को $9.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है, जिससे सड़कों, रेलवे और पुलों के विकास में मदद मिल रही है। 12 ऐतिहासिक रेल लिंक पुनः खोले गए हैं, और मैत्री एक्सप्रेस, भारत-बांग्लादेश तेल पाइपलाइन और नए सीमावर्ती आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

Ojaank Gurukul | IAS

रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग

संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत और बांग्लादेश सेना के बीच "संप्रीति" नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाता है।

गैर-आक्रामक सैन्य तकनीक

भारत बांग्लादेश को गश्ती नौकाओं और अन्य गैर-आक्रामक सैन्य उपकरण प्रदान करता है।

सैन्य प्रशिक्षण

बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों को एनडीए और आईएमए जैसे भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

सांस्कृतिक कूटनीति

छात्रवृत्ति, चिकित्सा पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।

भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर 1971 के युद्ध में भारत की भूमिका याद दिलाई। बांग्लादेशी छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में प्रायोजित किया जाता है और वीजा-मुक्त चिकित्सा पर्यटन की सुविधा प्रदान की जाती है।

आर्थिक संतुलन की रणनीति

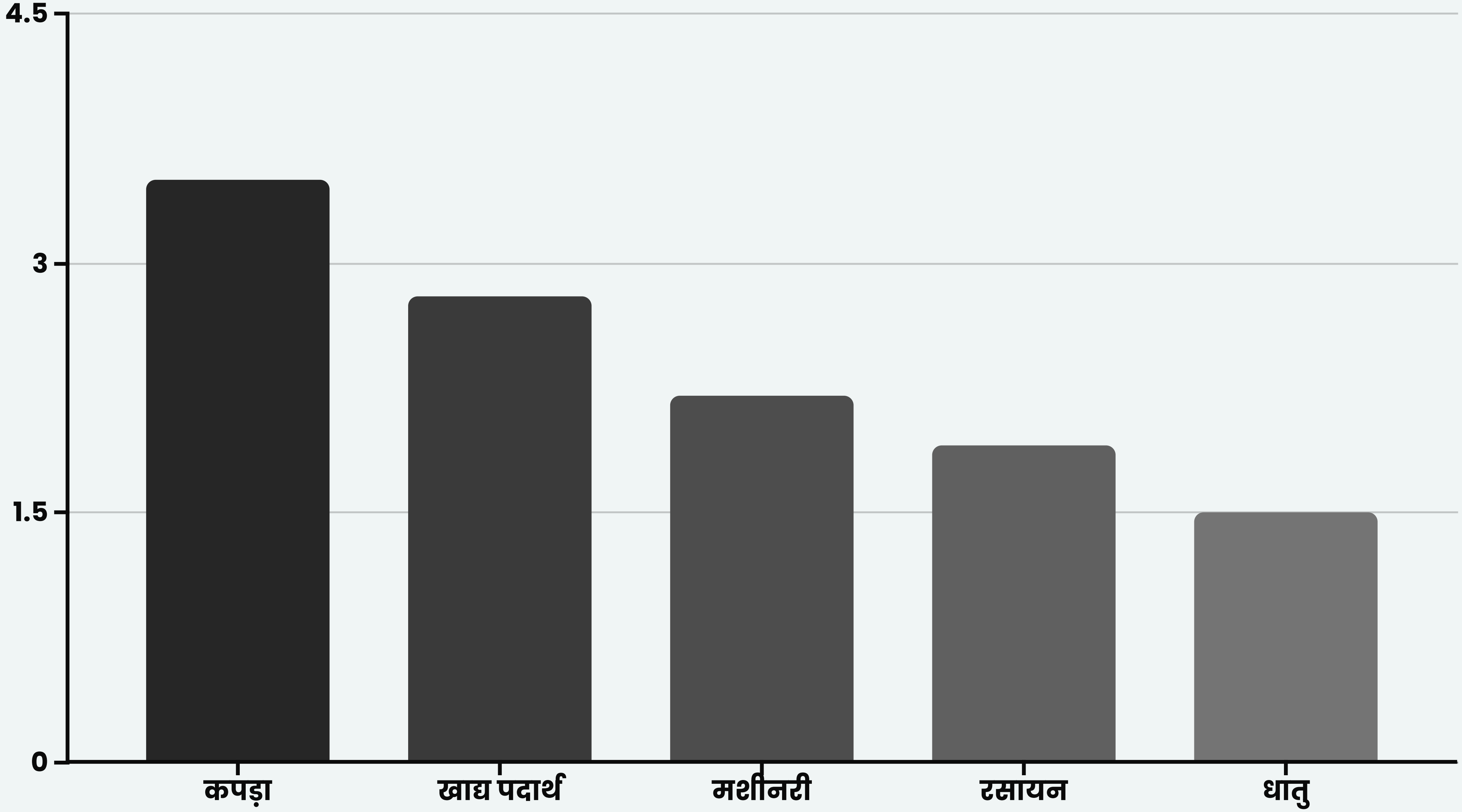

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर काम कर रहा है और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है।

भारत बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करके चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने से न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि रणनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे।

आगे की राह: भारत की रणनीति

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा

सड़कों, रडार कवरेज और अर्धसैनिक तैनाती के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को सुरक्षित करना। चीनी प्रभाव पर नज़र रखना और उसे नियंत्रित करना।

राजनयिक पहुंच बढ़ाना

बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश बढ़ाना। बिम्सटेक और भारत-जापान-बांग्लादेश त्रिपक्षीय जैसे क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना।

सॉफ्ट पावर कूटनीति

बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार को ट्रैक करना और काउंटर करना। विभिन्न मीडिया माध्यमों, छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना।

चीन रणनीतिक रूप से बांग्लादेश का उपयोग एक प्यादे की तरह कर रहा है, लेकिन भारत भी व्यापक आर्थिक, राजनयिक और सैन्य रणनीति अपना रहा है। बांग्लादेश वर्तमान में भू-राजनीतिक शतरंज बोर्ड पर एक स्विंग स्टेट बना हुआ है, और भारत को हर दिशा से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है।

Ojaank Gurukul | IAS

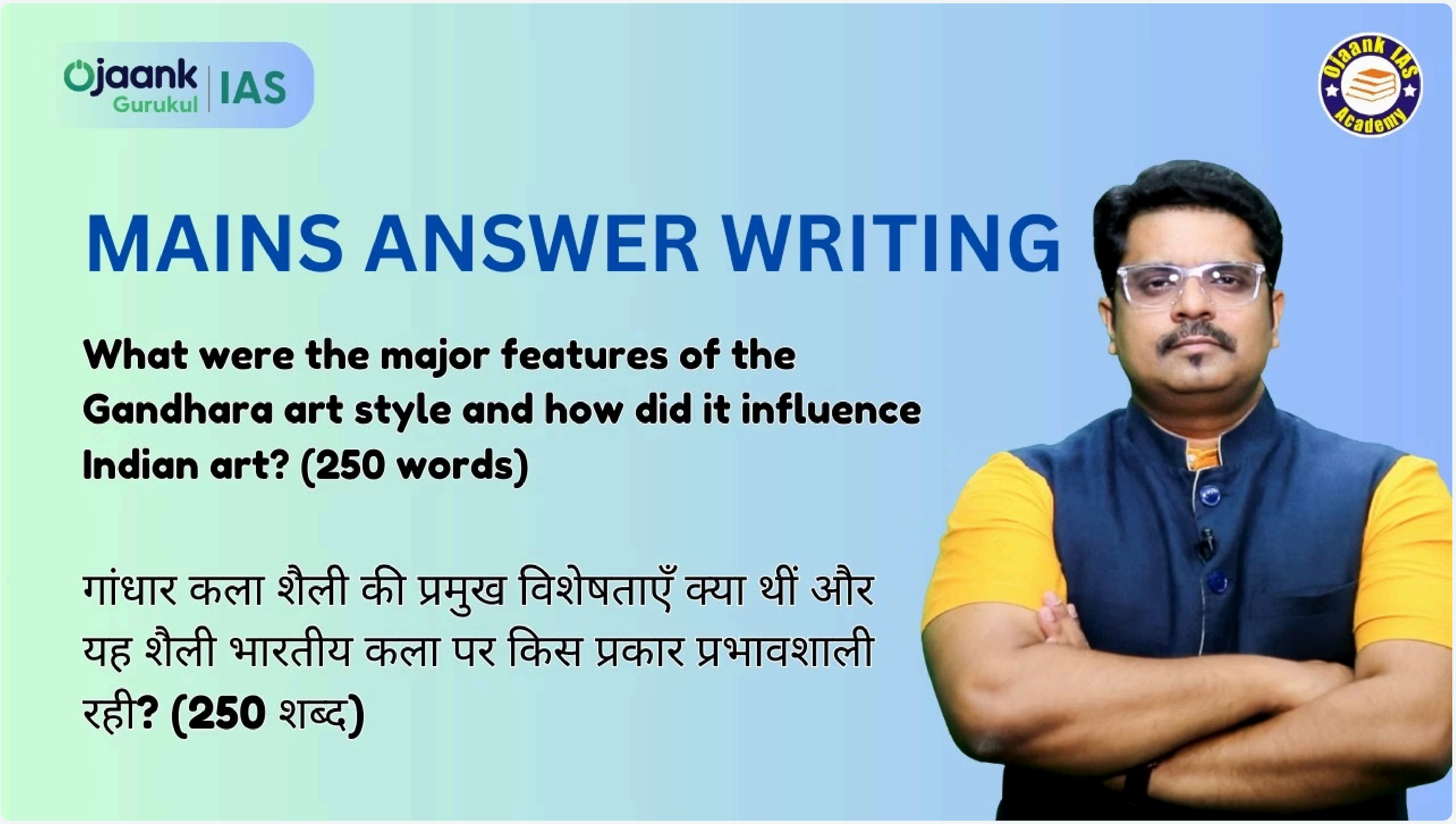

✍🏻 150–250 words | Think like a Civil Servant

CLICK TO JOIN 👇🏻

https://www.ojaank.com/blog/detail/examine-the-challenges-posed-by-uneven-demographic-changes-to-the-principle-of-proportional-representation-in-the-lok-sabha.-should-india-continue-periodic-delimitation-or-freeze-seat-allocation-assess-from-constitutional-and-political-perspectives

📞 **अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें: 8750711100/22/33/44/55, या WhatsApp करें:- 8285894079**

💪🏻 **Daily practice = Sure success**